RAMESH BAIS): (a) to (c) At present, no Hindi medium school is being changed into English medium school by the management of Bokaro Steel Plant.

Development Schemes for Workers in Steel Units

4394. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the social development schemes for the workers employed in steel units in Gujarat and Maharashtra and M.P.;

(b) the details thereof;

(c) whether Government have declared any special package plans for workers of steel units in Vidarbha and Kutch;

(d) if so, the main characteristics of this package;

(e) what is Government's plan for upliftment of workers belonging to rural and scheduled tribes community of the above districts; and

(f) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इस्पात इकाइयों की स्थापना

4395. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी हाल ही की विदेश यात्राओं के दौरान इस्पात क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत में इस्पात क्षेत्र में निवेश करने और सहयोग देने के लिये सहमत हुए हैं;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इस्पात संयंत्रों/इकाइयों की स्थापना के लिये चुना गया है;

(घ) क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य में किसी स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Revision in the rates of Royalty on Minerals

4396. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although royalty on minerals are revisable after every three years, Central Government make revision after five or six years;

(b) whether it is also a fact that delay in the revision of royalty results in considerable loss of revenue to the State Government; and

(c) whether Central Government are considering delegation of Powers to the State Governments to revise the rates of royalty and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) As per provisions of Section 9(3) of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Central Government may, by notification in the Official Gazettee, amend the Second Schedule so as to enhance or reduce the rate at which royalty shall be payable in respect of any mineral with effect from such date as may be specified in the notification provided that the Central Government shall not enhance the rate of royalty in respect of any mineral more than once during any period of three years. The delay in revision and implementation of rates of royalty on major minerals occurs due to procedural as well as administrative reasons. However, revision of rates may not necessarily also mean enhancement of rates and loss of revenues may occur only when there is delay in enhancement of royalty rates.

The Central Government constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Mines, Government of India with Mining Secretaries of major mineral producing states, Controller General, Indian Bureau of Mines and Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries etc. as members which considered apart from other aspects the suggestions for simplification of the procedure for effecting changes in revision of royalty rates of major minerals and ensuring

buoyancy of State revenues. The Committee has submitted its report to the Government and further necessary action has already been initiated.

राजस्थान में रामपुरा-अगूचा खान की क्षमता

4397. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में रामपुरा-आगूचा खान के संयंत्र की प्रति दिन क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या राजस्थान में एक नया "जिंक स्मैल्टर" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है तथा उसकी लागत और उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ग) "खनिज जिंक भंडार" के हवाई सर्वेक्षण संबंधी कार्य को किस सीमा तक पूरा कर लिया गया है और बाकी बचे कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) राजस्थान में रामपुरा-अगूचा खान स्थित अयस्क सज्जीकरण संयंत्र की क्षमता नवम्बर, 1997 में 3000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4500 टन प्रतिदिन कर दी गई है। नवम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक का औसत उत्पादन 3400 टन प्रतिदिन रहा।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले एक नये जस्ता प्रगालक के लिए प्रौद्योगिकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट को तैयार करने के बारे में मंजूरी दे दी है जिसकी उत्पादन क्षमता 60,000 टन से 1,00,000 टन प्रतिवर्ष होगी। इस नए जस्ता प्रगालक को स्थापित करने की सही लागत इस समय बता पाना संभव नहीं है।

(ग) हवाई सर्वेक्षण 17 नवम्बर, 1997 को शुरू किया गया था जो 13 अप्रैल, 1998 को पूरा हो गया। आंकड़ों का संसाधन/व्याख्या तथा जमीनी जांच संबंधी कार्य इस समय प्रगति पर है। हवाई सर्वेक्षण के संबंध में आंकड़ों को संसाधित करने का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

4398. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:
श्री गोविन्दराम मिरी:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इसका उत्पादन और मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार "सेल", "एस्सार", "टिस्को" और निजी क्षेत्र में किन्हीं अन्य इस्पात कंपनियों के उत्पादों की कीमतें कम करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जनवरी 1992 में इस्पात का नियंत्रण समाप्त करने की मांग, उत्पादन और मूल्य बाजार ताकतों द्वारा शासित होते हैं। प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात का मूल्य निर्धारित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। गौण उत्पादक 1992 से पहले भी, अपने मूल्य स्वंय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे। इस्पात के खुले बाजार मूल्यों में विगत एक वर्ष में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण यह है कि बाजार इस्पात की उच्च लागत को कायम रखने में सक्षम नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Performance of SAIL

4399. SHRI GURUDAS DASGUPTA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state;

(a) whether SAIL's performance during 1996-97 and 1997-98, shows continuous downslide in profitability;

(b) if so, how does it compare with the performance of other major steel plants in the country;

(c) whether Government have conducted any study to understand the reasons behind the downslide of the public sector Navaratna; and

(d) whether lack of leadership and directions are among the many causes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS):(a) and (b) The profits of Steel Authority of India Limited (SAIL) have decreased during 1996-97 and 1997-98. In the other major Integrated Steel Plants, viz., Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL) and Tata Iron & Steel Company (TISCO), RINL has registered an increase in losses and TISCO has